among others, recommended certain measures to be taken to increase the avenues of employment in the formal and organised sector as also in the small scale and medium size enterprises. It stressed the need to provide social security and labour protection to agricultural workers and to protect jobs in Indian Industry. It was also decided that the next session of the Indian Labour Conference should be convened in April, 1999 with the following items in the agenda:

—measures to reduce industrial sickness and to increase production and productivity.

—*measures to increase employment* opportunities.

(b) Yes, Sir.

(c) The Ministry of Labour is in agreement with the recommendation of Standing Labour Committee and has requested the Ministry of Finance for necessary action in this regard.

कर्मचारी भविष्य निधि अंशदानों को जमा न कराया जाना

2101. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्टील रौलरोलिंग मिलों में कार्यरत कितने श्रमिक और कर्मचारी भविष्य निधि योजना के सदस्य हैं;

(ख) उनके खातों में समय पर अंशदान राशि जमा न करने वाले मिल मालिकों के नाम क्या हैं;

(ग) उनसे कितनी राशि वसूल की जानी शेष है; और

(घ) इन मिल मालिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का क्या ब्यौरा है?

श्रम मंत्री (डा० सत्यनारायण जाटिया): (क) 3995

(ख) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स कानपुर स्टील एण्ड इंजीनियरिंग वर्क्स, भिलाई के श्री विनोद कुमार पंजाबी, मैसर्स शिव शक्ति री-रोलिंग मिल्स, रायपुर के श्री एल०पी० यादव और अन्यों तथा मै० हीरा स्टील मिल्स, रायपुर के श्री एच०पी० अग्रवाल ने कर्मचारी भविष्य निधि देयों की समय पर अदायगी में चूक की है। तदनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम की धारा 7-क के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार कानूनी कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी थीं और मैसर्स हीरा स्टील्स मिल्स, रायपुर के अलावा अन्यों से भविष्य निधि देयों की वसूली कर ली गयी है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने मैसर्स हीरा स्टील मिल्स पर बकाया देयों के निर्धारण की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

Eradication of Unemployment

2102. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the National Agenda for Governance proposes to eradicate unemployment;

(b) if so, the details of steps taken in this direction so far; and

(c) the employment opportunities created during the last one year?

THE MINISTER OF LABOUR (DR. SATYA NARAYAN JATIYA): (a) to (c) The National Agenda for Governance (NAG) stresses the need to reappraise and revitalise reforms through giving primacy to removal of unemployment and give to the entire development efforts a humane face with total eradication of proverty and removal of unemployment.

Under the direction from the Prime Minister, Five Special Action Plans (SAP) were formulated. These Plans pertain to:

(i) Doubling food production and making India hunger free in 10 years.

(ii) Expansion and improvement of social infrastructure—drinking water, housing, education, health care and sanitation—provision of drinking water to every settlement in the country within 5 years.